Skill development in textile sector

*5. SHRI SANJAY RAUT: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government is considering policy reforms to undertake skilling and re-skilling of textile workers for more employment generation in the country;

(b) if so, the details thereof;

(c) the details of programmes currently being implemented by Government for skill Development in various sectors of textile industry; and

(d) the details of funds allocated to various educational institutions and Non-Governmental Organisations (NGOs), etc. for the skill development pogrammes in Maharashtra State during the last two years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI AJAY TAMTA): (a) to (c) With a view to address the skilled manpower requirements of textile sector, the Ministry has been implementing Integrated Skill Development Scheme (ISDS) from 2010-11 to 2017-18. Under the scheme, 11.14 lakh persons have been trained out of which 8.43 lakh persons have been given employment. Out of total trained, 7.94 lakh were women, 2.32 lakh Scheduled Caste, 0.77 lakh Scheduled Tribes and 3176 persons were Divyangs.

In order to continue the endeavor of the Ministry in addressing the skill gap in the textile industry, a new scheme titled "Samarth" has been launched with a target to train 10 lakh persons in different job roles across all value chains (excluding Spinning and Weaving in the organized sector), over a period of three years upto 2019-20 with an outlay of Rs. 1300 crore. Overall framework for implementation is in alignment with the broad policy framework for skill development *viz.* Common Norms, National Skills Qualification Framework (NSQF) etc. adopted by Ministry of Skill Development & Entrepreneurship (MSDE). The scheme assistance will be provided to the training partner as per the Common Norms of the MSDE.

Handicrafts Sector:- For Skill Development in Handicrafts Sector, Office of Development Commissioner (Handicrafts) is implementing following schemes:

(I) Human Resource Development Scheme to provide qualified and trained workforce to the handicraft sector and also to create human capital for the sector in terms of trained cadre of designers.

(II) Design & Technology Upgradation Scheme to upgrade artisan's skills through development of innovative designs and prototype products for overseas market, revival of endangered crafts and preservation of heritage.

Handloom Sector:- Under National Handloom Development Programme (NHDP) and Comprehensive Handloom Cluster Development Scheme (CHCDS), Office of Development Commissioner (Handlooms) is providing training in technical area for upgradation of skill of the persons engaged in weaving activities.

Sericulture Sector:- Central Silk Board under the Ministry is imparting training for Skill enhancement to farmers, reelers, dyers, weavers, seed producers for boosting productivity and production of quality silk.

(d) The details of fund released to various Implementing agencies having training centers located in Maharashtra State under ISDS during last two years are given in the Annexure-I (*See* below). The details of fund released to various organizations for skill development programme in Maharashtra under Handicraft and Handloom sector during last two years are given in the Annexure-II.

Annexure-I

Funds released to Implementing Agencies conducted training in Maharashtra State under Integrated Skill Development Scheme (ISDS)

(In Rs. Lakhs)

Sl. No.	Implementing Agency	FY - 2016-17	FY - 2017-18	Total
1	Birla Cotsyn (India) Limited	265.0	93.5	358.5
2	IL&FS; Cluster Development Initiative Ltd.	12.4	4.8	17.2
3	National Textile Corporation Limited (NTCL)	17.2	55.1	72.3
4	Office of the TextileCommissioner	8.4	0	8.4
5	The Clothing Manufacturers Association of India (CMAI)	40.3	7.5	47.8
6	Wazir Advisors Private Limited	329.9	24.2	354.1
	TOTAL	673.2	185.1	858.3

Annexure-II

Details of funds released to various NGOs and Institutions for Skill Development Programmes in Maharashtra

I. **Under Handicrafts Sector**

(In Rs. lakhs)

Sl. No.	Name of Organization	Year 2016-17
1.	Rekha Rang Kala Trust , Aurangabad	13.80
2.	M/s Vidarbha Handicrafts Artisans Welfare Association, Nagpur	6.82
3.	M/s Adiwasi Swayam Kala Sansthan, Maharashtra	9.99
4.	M/s Shilpkar Bahudhiya Kalankari Mahila Sansthan, Nagpur	9.99
	Total	40.60

S. No.	Name of Organization	Year 2017-18
1.	M/s Jagriti Vikas Sansthan Jakadni Kalyan, Ratnagiri	9.99
2.	M/s Chadrk Swasthya Bahuddeshiya Sansthan, Sangli	19.97
3.	Council of Handicrafts Development Corporations	14.85
4.	Council of Handicrafts Development Corporations	14.85
5.	Council of Handicrafts Development Corporations	14.85
6.	Maharashtra Center for Entrepreneurship Development	4.80
7.	Council of Handicrafts Development Corporations	14.85
8.	Maharashtra Center for Entrepreneurship Development	4.80
	Total	98.96
	Grand Total (2016-17 & 2017-18)	139.56

II. Under Handloom Sector

(In Rs. lakh)

Name of organisation	FY - 2016-17	FY - 2017-18	Total
Weaver Service Centre, Nagpur	11.10	33.30	44.40

श्री संजय राउतः ऑनरेबल चेयरमैन सर, मेरा प्रश्न इस देश के लाखों-करोड़ों टेक्सटाइल वर्कर्स, हैंडलूम वर्कर्स, पावरलूम वर्कर्स से जुड़ा हुआ है, जिनको सरकार से बहुत बड़ी आस है और वे हमेशा मदद की गुहार भी लगाते हैं। सबसे पहले मैं सरकार से, मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा, मेरा प्रश्न है कि skilling and re-skilling of textile workers for more employment generation in the country, तो आपने टेक्सटाइल वर्कर की क्या डेफिनिशन की है, क्योंकि पावरलूम वर्कर्स तो बहुत तरह के काम करते हैं, हैंडलूम में काम करते हैं, पावरलूम में काम करते हैं। मुम्बई जैसा हमारा जो बड़ा शहर है, इसमें एक ज़माने में सबसे बड़ी आबादी टेक्सटाइल वर्कर्स की थी।

श्री सभापतिः संजय जी, क्वेश्चन पूछिए।

श्री संजय राउतः लाखों टेक्सटाइल मिलें आज वहां बंद हो चुकी हैं, जिससे अनेक वर्कर बेरोज़गार हो गए हैं। आपने उन कामगारों को कौशल प्रदान करने हेतु जो योजना चलाई है, मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि वहां मिलें बंद होने की वजह से जो लोग बेरोज़गार हो गए हैं, उनके बच्चे भी बेरोज़गार हो गए हैं, नई स्कीम के तहत रोज़गार देने के लिए क्या आप कोई नई योजना बनाने जा रहे हैं?

श्री अजय टम्टाः सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, खास तौर पर टैक्सटाइल के क्षेत्र में स्किल करने की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, जिसके लिए सरकार के द्वारा 2010 से लेकर 2017 तक योजनाएं चलाई गई थीं। हमने उत्तर में भी बताया है कि इन योजनाओं के अंतर्गत 11,14,545 लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। वहीं प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संगठन को यह जिम्मेदारी भी दी गई है कि ट्रेनिंग के बाद उन्हें रोज़गार भी उपलब्ध कराना है। ...**(व्यवधान)**... महोदय, मैं उसी पर आ रहा हूं। यदि फिर भी कोई सवाल रहता है, तो आप बाद में पूछिए। इस योजना के अंतर्गत हमने 8,93,082 लोगों को अब तक रोज़गार दिया है। माननीय सदस्य ने पूछा है कि हमारे विभाग द्वारा क्या कोई नई योजना उन्हें रोज़गार देने हेतु चलाने पर विचार किया जा रहा है, तो मैं बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन में हम एक नई योजना 'समर्थ' के रूप में जल्दी शुरू करने वाले हैं, जिसमें हमने बहुत पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई है। उस पारदर्शी प्रक्रिया के अतिरिक्त हमने इसमें 1300 करोड़ रुपए का परिव्यय भी रखा है। इस योजना का 2017 से लेकर 2020 तक कामगारों को लाभ मिलेगा। दस लाख लोगों को हम इसमें स्किल्ड करेंगे, उनके कौशल का उन्नयन करेंगे। उस योजना की

बहुत सी गाइडलाइन्स को हम पूरा करेंगे। ऐसा करते हुए, हमने 25.5.2018 से लेकर 25.6.2018 तक, online उनकी formalities के संबंध में सुझाव मांगे और 10.7.2018 तक, जो अभी गया है, हमने उसकी समीक्षा की है। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय राउतः महोदय, मेरा प्रश्न कुछ अलग था और माननीय मंत्री जी ने उससे अलग हटकर रिप्लाई दिया है। मैंने मुम्बई के टैक्सटाइल मिल वर्कर्स और उनके बच्चों के बारे में स्पेसिफिक प्रश्न पूछा था, जिसका जवाब मुझे मंत्री जी से नहीं मिला है। सरकार की ओर से यहां कहा गया कि इस स्कीम में अब तक लगभग 11,14,545 लोगों को ट्रेन किया गया है और 8 लाख के आसपास लोगों को रोज़गार भी दिया है। महाराष्ट्र में भिवंडी सबसे बड़ा हैंडलूम का पब है। उसके बाद इचलकरंजी है, जिसे महाराष्ट्र का मैनचेस्टर कहा जाता है। उसके बाद हमारे यहां पलछिन है, येवला है, जहां बुनकर साड़ियां बनाते हैं। यदि वहां के सभी वर्कर्स तक आपकी योजना का लाभ न पहुंचे तो लाखों-करोड़ों रुपए, जो इन योजनाओं पर एन.जी.ओ. के माध्यम से आप खर्च कर रहे हैं, उसका लाभ उन्हें कब तक मिलेगा?

MR. CHAIRMAN : Now, Madam Minister. The question was general but the hon. Member has asked a specific question. If you have answer, please give it to him now; otherwise collect the information and give it to the hon. Member.

वस्त्र मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी): माननीय सदस्य ने यहां विशेष रूप से महाराष्ट्र के संदर्भ में, पैटन कला के संदर्भ में, भिवंडी और इचलकरंजी के संदर्भ में प्रश्न पूछा है। इससे पहले मुम्बई के मिल वर्कर्स और उनके बच्चों के संदर्भ में प्रश्न पूछा। जैसा माननीय राज्य मंत्री जी ने उन्हें अवगत कराया, इस संदर्भ में हमारी भूमिका यह रही है कि हम इंडस्ट्री पार्टनर, एन.जी.ओज़ और प्रदेश की सरकारों के साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाते हैं। वर्तमान में 'समर्थ' नाम की जो स्कीम प्रेषित की गई है, उसके संबंध में 14 मई को देश भर में टेक्सटाइल से संबंधित सभी महानुभावों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र के, विशेषकर भिवंडी और इचलकरंजी के कई representatives भी उपस्थित हुए थे। पिछले प्लान के अंतर्गत, हमारी स्कीम में जो placement and training हुई है, उसमें महाराष्ट्र के लगभग 37,000 से ज्यादा लोगों की training हुई है। भिवंडी ठाणे जिले में आता है, जहां 17,850 से ज्यादा लोगों की training हुई है। इचलकरंजी, कोल्हापुर जिले में है और वहां पर लगभग 136 से ज्यादा लोगों की पिछले समय में ट्रेनिंग हुई है। जहां तक इस बात का संबंध है कि जो मिल वर्कर रह चुके हैं, उनके बच्चों को अगर ट्रेनिंग की दरकार हो, तो वर्तमान में इस स्कीम के अंतर्गत विशेष रूप से प्रावधान है कि किसी एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आ सकते हैं। हमने विशेष प्रावधान यह भी किया है कि माननीय प्रधान मंत्री की जो 'स्टार्ट-अप-इंडिया' की सोच है, उससे जोड़ते हुए जो first-time-entrepreneur हैं या बनना चाहते हैं, उनको हम मुद्रा योजना से भी जोड़ रहे

हैं ताकि अगर वे ट्रेनिंग के बाद स्वतः काम करना चाहें, तो उसकी भी सुविधा भारत सरकार उपलब्ध कराती है।

श्री सभापतिः श्री दिग्विजय सिंह।

श्री दिग्विजय सिंहः माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्किलिंग और री-स्किलिंग के मामले में हैंडलूम के बारे में बात की, handicraft के बारे में बात की, sericulture के बारे में बात की, लेकिन खादी उद्योग शायद उनकी प्राथमिकता में नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि खादी के मामले में कौन-सी स्किलिंग और री-स्किलिंग की योजना बना रहे हैं, क्योंकि खादी उद्योग में जब तक चरखे की री-स्किलिंग नहीं की जाएगी, तब तक उसकी economic viability नहीं सुधरेगी? आप खादी के कपड़े के उद्योग में स्किलिंग और री-स्किलिंग की कौन-सी योजना बना रहे हैं?

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानीः सर, माननीय सदस्य शायद इस बात से अवगत होंगे कि खादी का विभाग एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, टैक्सटाइल मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन भारत सरकार का स्किलिंग का जो प्रोग्राम है, उसमें इस तरह के सारे विशेष प्रावधान किए गए हैं कि खादी included बहुत सारी चीजों में ट्रेनिंग NSQF-compliant courses में दी जाती है। 'समर्थ' नाम की स्कीम में भी हम लोग स्किल मिनिस्ट्री के साथ मिल कर NSQF-compliant सारे courses दे रहे हैं और विशेषतः हथकरघा और बुनकर अगर इसमें काम करना चाहें, तो डेवलपमेंट कमिश्नर, हैंडलूम के माध्यम से देश में 28 वीवर सर्विस सेंटर्स हैं, जिनके अंतर्गत हमारे बुनकर समाज के जितने भी प्रतिनिधि हैं, वे आकर इसमें विशेष रूप से स्किलिंग प्राप्त कर सकते हैं।

श्री सभापतिः श्रीमती कहकशां परवीन जी।

श्रीमती कहकशां परवीनः सभापति महोदय, भागलपुर, रेशमी शहर के नाम जाना जाता है और आज वह अपनी पहचान खोता जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहती हूं कि रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वहां कितने बुनकरों को प्रशिक्षण दिया गया और उनका कितना लाभ हुआ? क्या सरकार ने इसके आकलन के लिए कोई टीम बनाई कि जो प्रशिक्षण दिए हुए बुनकर हैं, उनकी आर्थिक स्थिति में कितना सुधार हुआ?

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानीः सर, भागलपुर में विशेष रूप से जो सिल्क का उत्पादन होता है, जो बुनकर परिवार इससे जुड़े हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान मात्र 'समर्थ' के माध्यम से नहीं है, बल्कि सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड के अंतर्गत भी बुनकर परिवारों को इससे और विशेषतः जो इसकी फार्मिंग से जुड़े हैं, ऐसे समुदाय को बहुत सारी सहूलियतें और बहुत सारा समर्थन मिलता है। विशेष रूप से केबिनेट ने

हाल ही में सिल्क इंडस्ट्री के लिए 'सिल्क समग्र' नाम की एक स्कीम को प्रेषित किया है, राष्ट्र को समर्पित किया है। इसमें 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आबंटन हुआ है। डेवलपमेंट कमिश्नर, हैंडलूम के ऑफिस के माध्यम से भी, वीवर सर्विस सेंटर्स के माध्यम से भी और प्रदेश के अधिकारियों के साथ मिलकर... विशेषतः हमने पहली बार हैंडलूम वीवर्स के लिए प्रदेश की सरकारों के साथ एक विशेष बैठक की और उसमें हमने विशेष प्रदेश की सरकारों से आग्रह किया कि अगर आपको किसी एक खास विशेष इलाके के लिए कोई प्रावधान चाहिए और ज्यादा समर्थन चाहिए, तो आप अपना मसौदा हमारे पास भेज सकते हैं। हम आशावादी हैं कि प्रदेश की सरकार से हमारे पास वह मसौदा आएगा।

MR. CHAIRMAN: Thank you.

Hon. Members, who had given Zero Hour notices and which could not be taken up, if they are interested in raising their submissions, they can repeat their notices. As an exception, I have decided to allow them tomorrow. So, all those who are interested can give fresh notices again.

Now, Shri Naresh Gujral.

SHRI NARESH GUJRAL: Sir, I commend the Government for laying so much emphasis on the skilling programme, especially in the textile industry because, after agriculture, this is the largest employment generator in the country. But, there is only one issue that after skilling — while the Government has made schemes to incentivise companies to hire these people — there is one caveat that if a company hires a person, then, for the first couple of years, the provident fund and the ESI is paid by the Government; however, if that person is reemployed somewhere else then that facility is withdrawn. Sometimes, a person finds a job for six months. But when he moves to the second company, this is withdrawn.

MR. CHAIRMAN: Right.

SHRI NARESH GUJRAL: So, I hope the Minister would look into it because this is disincentivising employment generation.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, incentives given to companies or to entrepreneurial ventures come from taxpayers' money and, hence, come with caveats.